

Subject: Economics

Class: B.A Part I (Paper II)

Topic: Keynesian Theory of Employment
(कीन्स का रोजगार सिद्धान्त)

By:

EKATA KUMARI

Guest Faculty

(Assistant Professor)

Mohila College Saralaganj, Patna

Email ID:

bhridevajakata@gmail.com

केन्ज के रोजगार सिद्धांत :-

केन्ज का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल के लिए कार्यशील होता है। क्योंकि केन्ज यह मान लेते हैं कि पूंजी की मात्रा, जनसंख्या व-प्रस शक्ति, तकनीकी ज्ञान, प्रसिकों की कार्यकुशलता आदि में कोई वृद्धि नहीं होती। यही कारण है कि केन्ज के सिद्धांत में रोजगार की मात्रा, राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन के स्तर पर ही निर्भर करती है क्योंकि यदि पूंजी की मात्रा, तकनीकी ज्ञान, प्रसिकों की कार्यकुशलता आदि स्थिर रहे तो अधिक प्रसिकों को काम में लगाकर ही राष्ट्रीय आय बढ़ाई जा सकती है। अतः केन्ज के अल्पकाल में राष्ट्रीय आय के अधिक होने का अर्थ है रोजगार की अधिक मात्रा और राष्ट्रीय आय के कम होने का अर्थ है रोजगार की कम मात्रा। अतः केन्ज का सिद्धांत रोजगार निर्धारण का सिद्धांत भी है और राष्ट्रीय आय निर्धारण का भी। परन्तु रोजगार तथा राष्ट्रीय आय दोनों को निर्धारित करने वाले तत्व समान हैं। केवल उनके

निर्धारण की व्याख्या के लिए प्रयोग की गई
रेखाकृतियों का ही अंतर है।

रोजगार के निर्धारण के विषय में केन्ज का आधा-
रभूत विचार समर्थ मांग का नियम है। किसी
देश में अल्पकाल में रोजगार की मात्रा वस्तुओं
के लिए समस्त समर्थ मांग पर निर्भर करती है।
समस्त समर्थ मांग जितनी अधिक होगी रोजगार
की मात्रा उतनी अधिक होगी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था
में रोजगार का निर्धारण समस्त पूर्ति कीमत और
समस्त मांग कीमत द्वारा होगा।

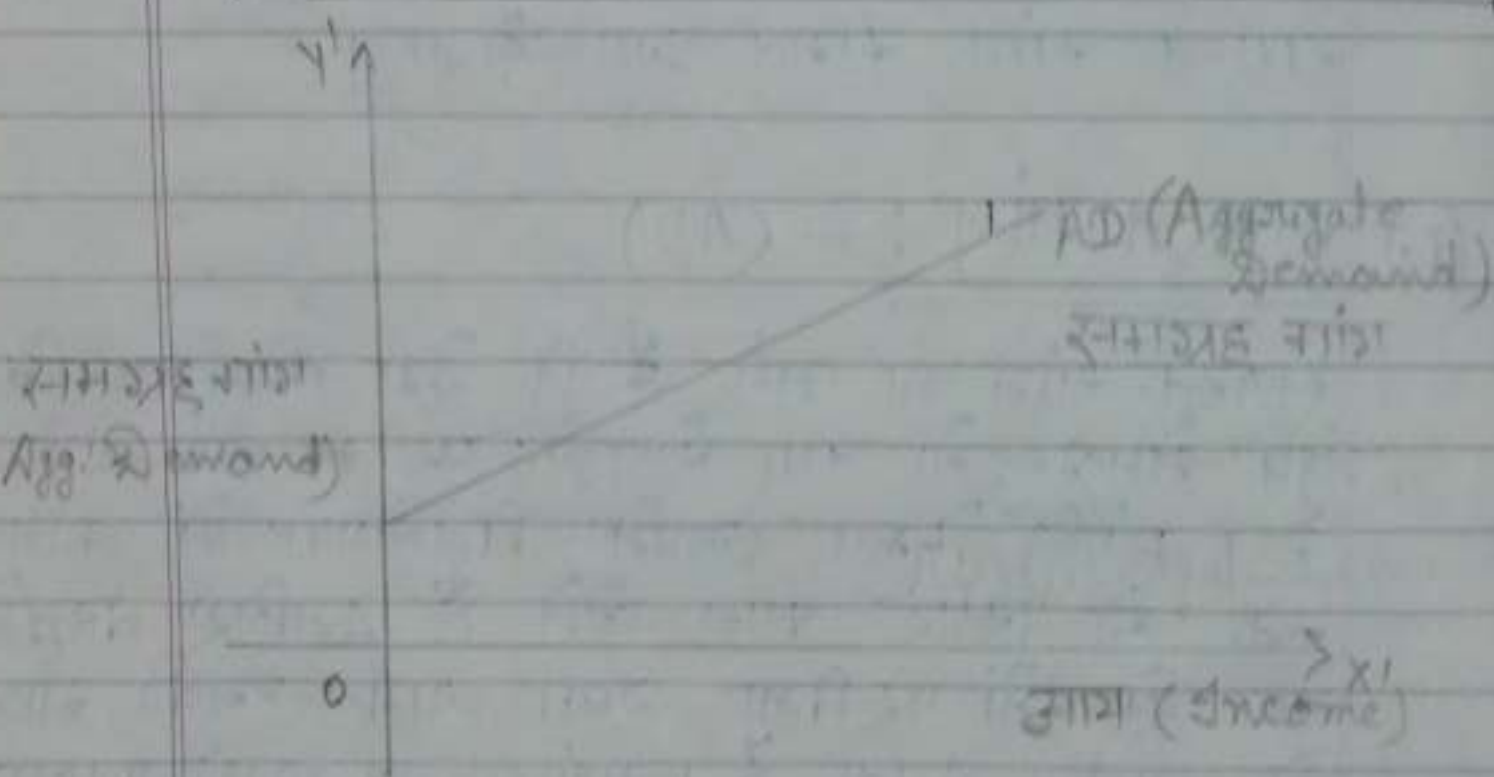
I. समस्त मांग :- (AD)

समस्त मांग का अर्थ है कि देश की जनता एक
वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं पर कितना व्यय करती
है। क्योंकि केन्ज अपने विश्लेषण में कीमत-
स्तर को स्थिर मान लेते हैं। इसलिए वस्तुओं
तथा सेवाओं पर किया गया व्यय उनकी मात्राओं
को व्यक्त करता है। अर्थात् जब अर्थव्यवस्था में
प्रमियों की किसी एक संख्या को रोजगार पर
लगाने पर जितना उत्पादन होता है, उसको बेचने
से अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगी कुल जितनी राशि
वास्तव में प्राप्त करने की आशा करते हैं, वह
रोजगार के उस स्तर पर की समस्त-मांग कीमत

होती है। दूसरे शब्दों में, जब आर्थिक व्यवस्था में रोजगार का कोई स्तर हो तो उस समय उस स्तर पर हुए कुल उत्पादन के बिकने से जितनी कुल राशि प्राप्त होने की आशा हो, वही कुल राशि रोजगार के उस स्तर पर समस्त मांग अथवा समस्त मांग कीमत होगी।

$$\text{कुल मांग} = \text{उपभोग व्यय} + \text{निवेश व्यय}$$

$$AD = C + I$$



समग्र मांग और कीमत स्तर के बीच विपरीत संबंध है। AD वक्र X' पर उत्पाद के स्तर और Y' पर कीमत स्तर को दर्शाया गया है। इन दोनों के बीच विपरीत संबंध है। AD वक्र प्रवृत्तात्मक वक्र होती है। हम समस्त मांग अथवा

समस्त मांग कोमल एक वक्र के रूप में दर्शा सकते हैं।
 अधिक रोजगार प्रदान करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है, अर्थव्यवस्था की वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए समस्त मांग बढ़ेगी। इसका अर्थिप्राय यह है कि जैसे देश में रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है जनता द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय भी बढ़ता है। इसलिए समस्त मांग वक्र रोजगार के बढ़ने पर ऊपर की ओर चढ़ता है। यदि कुल मांग अथवा व्यय में वृद्धि से रोजगार में समान अनुपात से वृद्धि होती है तो समस्त-मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ सरल रेखा के आकार का होगा।

केन्ज का एक महत्वपूर्ण योगदान समस्त मांग की धारणा है जो परंपरागत विचारधारा से काफी भिन्न है। यदि हम सरकार द्वारा व्यय तथा निर्यात द्वारा उत्पन्न मांग को विश्लेषण में सम्मिलित न करें तो केन्ज के अनुसार समस्त मांग के दो घटक हैं :-

- (a) लोगों की उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग।
- (b) उद्यमकर्त्ताओं द्वारा निवेश पर किया गया व्यय।

श्रम के लिए रोजगार में वृद्धि होने पर तथा उसके फलस्वरूप उत्पादन के बढ़ने पर समस्त मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ेगा और सामान्यतः रोजगार व उत्पादन में वृद्धि के साथ इसकी ढाल घटती जायेगी जैसा कि ऊपर रेखाचित्र में दिखाया गया है। अतः समस्त मांग वक्र का स्तर तथा आकृति एक ओर तो उपभोग पर व्यय और निवेश पर व्यय पर निर्भर करती है। यदि उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है तथा निवेश व्यय कुल आय से स्वतंत्र है जैसा कि केन्ज महोदय की मान्यताएँ हैं तो समस्त मांग का वक्र सरल रेखा के प्रकार का होगा। किंतु जैसा कि रेखाकृति में दिखाया गया है समस्त मांग के वक्र की ढाल कुल रोजगार में वृद्धि के साथ घटती जाती है जो कि इस आधार पर बनाया गया है कि आय व रोजगार में वृद्धि के साथ समस्त मांग में वृद्धि घटती दर से होती है।

समग्र मांग के निर्धारक तत्व :-

समग्र मांग के मुख्य चार निर्धारक तत्व हैं। जो इस प्रकार हैं :-

(क) निजी उपभोग :- निजी उपभोग में एक देश के सभी गृहस्थों द्वारा वस्तुओं

और सेवाओं की कुल मांग निजी उपभोग कहलाती है। यह प्रयोज्य आय और उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है।

(b) निजी निवेश :- इससे तात्पर्य निजी निवेश कर्ता (I) द्वारा पूंजी वस्तु के मांग से है। जैसे - * घुंजी यंत्र समंत्र
* गृहो उपयोगी संरचना
* भंडार ।

(c) सरकारी व्यय :- सरकार द्वारा कुल वस्तुओं और सेवाओं की मांग इसमें शामिल है जो सरकारी नीतियों पर आधारित होती है। (G)

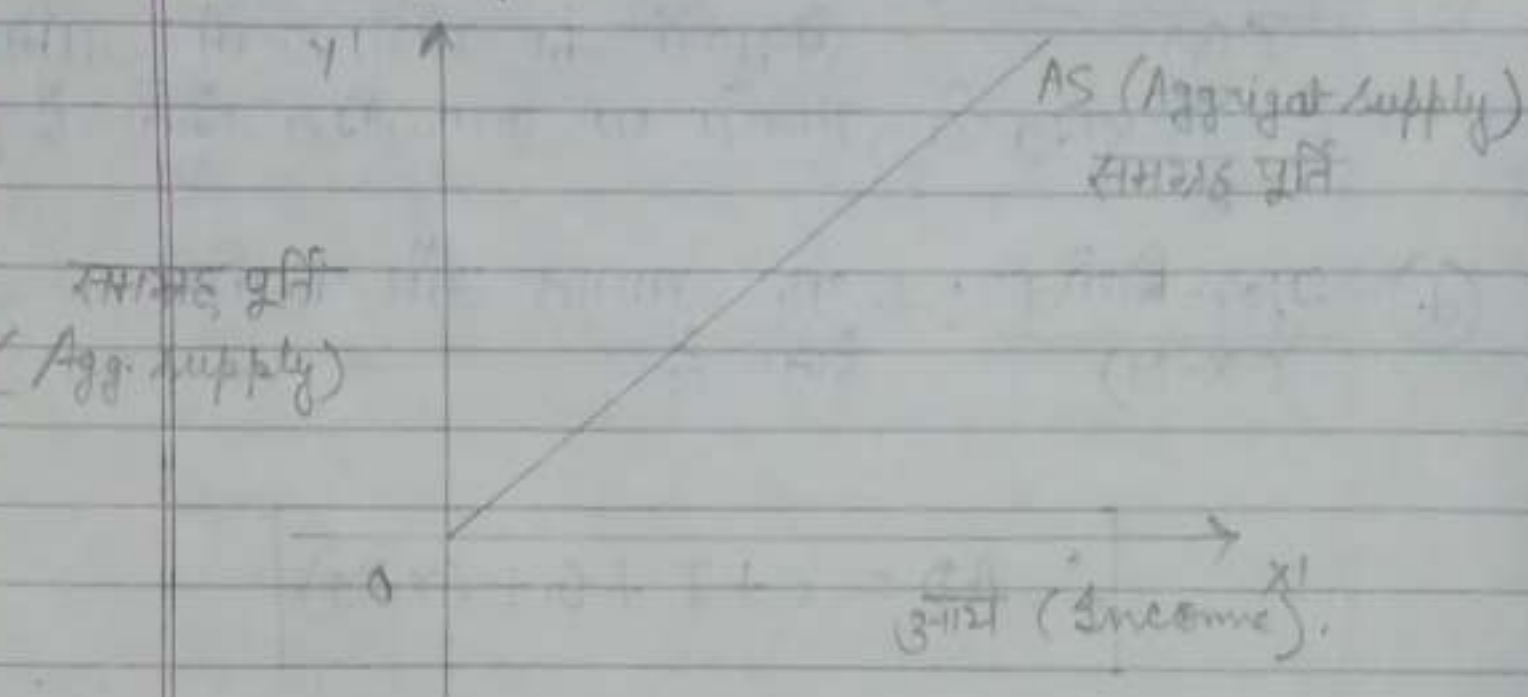
(d) शुद्ध-निर्यात :- यह आयात और निर्यात का अंतर होता है। (X-M)

$$\therefore AD = C + I + G + (X - M)$$

(ii) सामग्र्य पूर्ति :- (AS)

सामग्र्य पूर्ति अथवा जिसे सामग्र्य पूर्ति कीमत कहते हैं। स्थूल रूप से हम यह कहेंगे कि जब अर्धव्यवस्था के सभी उत्पादी प्रसिक्तों की किसी एक संख्या तक

को काम पर लगाते हैं, तो उन्हें उन प्रमियों द्वारा बनायी गई कुल वस्तुओं के लिए जितनी कुल राशि अवश्य मिलनी चाहिए ताकि वे उन प्रमियों को कार्य अथवा रोजगार पर लगाये रखें, वह समस्त पूर्ति कीमत है। साधारण शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि, अर्थव्यवस्था में प्रमियों की किसी एक संख्या को रोजगार में लगाने पर उन प्रमियों द्वारा किये गये समस्त उत्पादन की कुल लागत को अर्थव्यवस्था की समस्त पूर्ति कहते हैं। इसे एक रेखाचित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं :-



चित्र, में X पर आय और Y पर समग्र पूर्ति को दर्शाया गया है और AS समग्र पूर्ति वक्र है। जैसा कि ऊपर चित्र में दर्शाया गया है। समग्र पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर बाएँ से दाएँ की ओर ऊपर उठती हुई होती है।

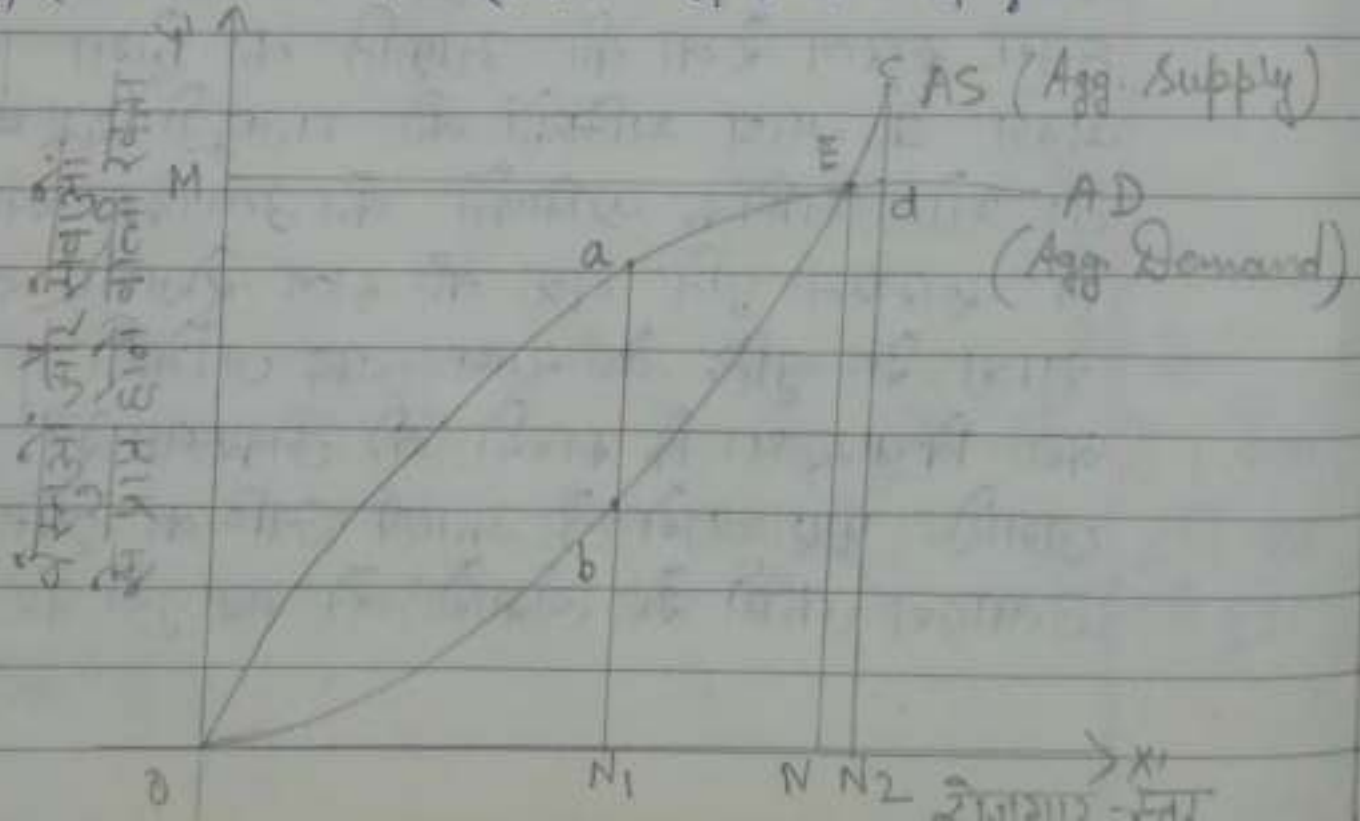
समस्त पूर्ति वक्र अन्ततः उत्पादन संबंधी भौतिक अथवा तकनीकी स्थितियों पर निर्भर करता है। उत्पादन संबंधी ये भौतिक या तकनीकी दशाएँ प्रायः अल्पकाल में नहीं बदलती हैं। जब ये तकनीकी दशाएँ दी गई हों, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक श्रमिकों को कार्य में लगाया जाता है। किंतु जब उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाये जाते हैं तो उत्पादन पर अधिक लागत उठानी पड़ेगी। उत्पादन हेतु जब अधिक श्रमिकों को कार्य अथवा रोजगार पर लगाया जाता है तो उस पर अधिक लागत उठानी पड़ेगी। अतः उत्पादन कार्यों में पहले से अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जाएगा जब व्यवसायियों को यह आशा होगी कि उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों पर अधिक व्यय किया जाएगा जिससे उठाई गयी अतिरिक्त लागत की पूर्ति हो सके। समस्त पूर्ति वक्र की ढाल कि दायीं ओर ऊपर चढ़ेगा। समस्त पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ सरल रेखा की आकृति का होगा। यदि रोजगार बढ़ने के साथ श्रमिकों की मजदूरी दर बढ़ जाती है तो भी अधिक श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगाने से समस्त पूर्ति वक्र की ढाल रोजगार तथा उत्पादन मात्रा में वृद्धि के साथ बढ़ जायेगी। किंतु केन्ज का विचार था कि मन्दी की अवस्था में भीषण बेरोजगारी पाए जाने के कारण अधिक श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगाने से मजदूरी दर स्थिर रहेगी।

$$\text{कुल पूर्ति} = \text{उपभोग व्यय} + \text{बचत}$$

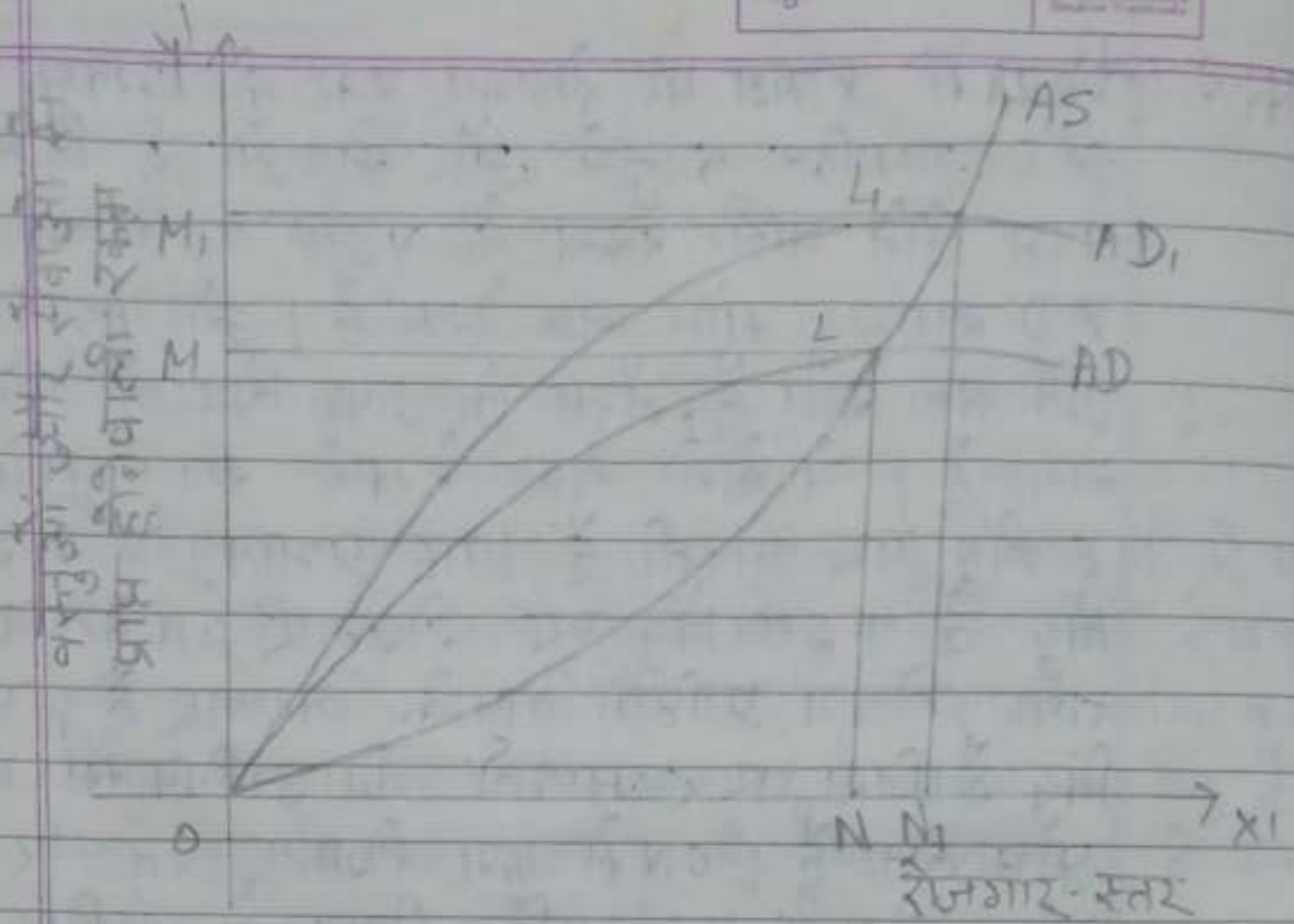
$$AS = C + S$$

III. रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण :-

यदि कुल मांग वक्र तथा कुल पूर्ति वक्र की रेखाएँ तैयार की जायें तो जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं वह प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु वह है जो यह दर्शाता है कि रोजगार के एक विशेष स्तर पर कुल मांग - कीमत तथा कुल पूर्ति - कीमत एक - दूसरे के बराबर है। यह अल्पकालीन संतुलन बिंदु है जो रोजगार - स्तर को निर्धारित करता है। इसे एक रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है, जो है :-



चित्र में x अक्ष पर रोजगार स्तर को दिखाया गया है और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम को y अक्ष पर दिखाया गया है। AD समग्रह मांग वक्र रेखा है। और AS समग्रह पूर्ति वक्र रेखा है, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ये दोनों वक्र - रेखाएँ एक - दूसरे को E बिंदु पर काटती हैं। यह प्रभावपूर्ण मांग की बिंदु है। इस बिंदु पर रोजगार ON के बराबर तथा विक्रय प्राप्ति OM के बराबर हैं। यह वह बिंदु है जिस पर उद्यमकर्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ON से कम रोजगार - स्तर पर कुल मांग - कीमत कुल पूर्ति - कीमत से अधिक है। प्राप्त होने वाली रकम उनकी लागत से अधिक है तो ऐसी स्थिति में उद्यमकर्ता को रोजगार तथा उत्पादन बढ़ाना चोहेगा। जब E बिंदु के पश्चात् AD वक्र AS वक्र के दाईं ओर चला जाता है तो कुल पूर्ति कुल मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में उद्यमकर्ता को घाटा होगा और उद्यमकर्ता रोजगार बढ़ाने के बजाय मजदूरों की फँदनी करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि कुल रोजगार ON तक नहीं पहुँच जाता। स्पष्ट है कि रोजगार E बिंदु तक ही बढ़ता है। इस बिंदु पर समूची अर्थव्यवस्था में रोजगार संतुलन की अवस्था में होगा।



AS वक्र पहले धीरे-धीरे ऊँचा उठता है। यदि विक्री प्राप्ति बढ़ती है तो रोजगार भी बढ़ जाता है। परन्तु बाद में लागतों में वृद्धि हो जाने पर AS वक्र सीधा ऊपर उठने लगता है, क्योंकि पूर्ति की मूल्य-सापेक्षता घटती जाती है। यह पूर्ण-रोजगार का बिंदु है।

यहाँ यह बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि E अथवा प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु पर कुल मांग-कीमत और कुल पूर्ति-कीमत एक-दूसरे के बराबर हो जाती है और रोजगार-संतुलन स्थापित होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इस बिंदु पर यह संतुलन पूर्ण-रोजगार के स्तर पर ही हो।

ऊपर चित्र में AS तथा AD वक्र एक-दूसरे को L बिंदु पर काटते हैं। इस बिंदु पर रोजगार ON के बराबर है और बिक्री प्राप्ति OM होने की आशा है। परन्तु जैसा कि AS वक्र से ज्ञात होता है, पूर्ण रोजगार तब होगा जब रोजगार का स्तर ON_1 के बराबर हो। स्पष्ट है कि ON रोजगार-स्तर संतुलन की अवस्था में तो है परन्तु अभी तक अर्धव्यवस्था में NN_1 के बराबर बेरोजगारी है। पूर्ण-रोजगार संतुलन प्राप्त करना अभी संभव हो सकता है, जब ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हों कि बिक्री-प्राप्तियों में PM_1 के बराबर वृद्धि हो जाये।

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल से संबंधित है। पूँजी की उपलब्ध मात्रा, उत्पादन की तकनीक, श्रम की कार्यक्षमता, जनसंख्या का आकार, व्यवसायिक संगठन का स्वरूप आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें स्थिर मान लिया गया है। यह मान्यता केवल अल्पकाल में ही लागू होती है।